

वैश्विकि दलहन सम्मेलन

प्रलमिस् के लयि:

भारतीय राषट्रीय कृषि सहकारी वपिणन संघ लमिडिड, ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन, शीर्ष दाल उत्पादक राज्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, राषट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन (NFSM)-दलहन, प्रधानमंत्री अननदाता आय संरक्षण अभयान (PM-AASHA) योजना, मूल्य स्थरिीकरण नधि

मेन्स के लयि:

भारत में दलहन उत्पादन की स्थिति, भारत में दलहन उत्पादन से संबंधित चिंताएँ

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय राषट्रीय कृषि सहकारी वपिणन संघ लमिडिड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd- NAFED) और ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन (GPC) द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विकि दलहन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन वार्षिकि रूप से किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से दलहन उत्पादक, संसाधक तथा व्यापारी भाग लेते हैं।

- भारत ने वर्ष 2027 तक **दलहन** उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें कृषि में वृद्धि और कृषकों को नई कस्मि के बीजों की आपूर्तिकराने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन क्या है?

- वैश्विकि दलहन महापरसिंघ (ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन- GPC) दलहन उद्योग मूल्य शृंखला के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें उत्पादक, शोधकर्ता, रसद आपूर्तिकर्ता, व्यापारी, निर्यातक और आयातक के साथ-साथ विभिन्न सरकारी निकाय, बहुपक्षीय संगठन, संसाधक/प्रोसेसर, कैनर्स और उपभोक्ता शामिल हैं।
 - इसमें 24 राषट्रीय संघ और 500 से अधिक नज्ी क्षेत्र के सदस्य शामिल हैं।
- यह दुबई में स्थित है और इसे दुबई मल्टी क्मोडिटी सेंटर (DMCC) द्वारा लाइसेंस प्राप्त है।

भारत में दलहन उत्पादन की स्थिति क्या है?

- परचिय: भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक (वैश्विकि उत्पादन का 25%), उपभोक्ता (विश्व खपत का 27%) तथा आयातक (14%) है।
 - खाद्यान्न के अंतरगत आने वाले क्षेत्र में दलहन की हसिसेदारी लगभग 20% है तथा देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान लगभग 7-10% है।
- शीर्ष दलहन उत्पादक राज्य: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक।
- मुख्य कस्मिमें: दलहन का उत्पादन संपूरण कृषि वर्ष में किया जाता है।
 - रबी फसलों को बुवाई के दौरान हलकी ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, वानस्पतिक से लेकर फली बनने तक ठंडी जलवायु की और परपिकवता/कटाई के दौरान गरम जलवायु की आवश्यकता होती है।
 - खरीफ दलहनी फसलों को बुवाई से लेकर कटाई तक उनके पूरे जीवनकाल के दौरान गरम जलवायु की आवश्यकता होती है।
 - रबी सीजन की दलहन (कुल उत्पादन में 60% से अधिक योगदान): चना, चना (बंगाल चना), मसूर, अरहर।
 - खरीफ सीजन की दलहन: मूंग (हरा चना), उड़द (काला चना), तूर (अरहर दाल)।



■ **प्रमुख निर्यात गंतव्य (2022-23):** बांग्लादेश, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और नेपाल ।

■ **महत्त्व:**

- पोषण संबंधी पावरहाउस: दालें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होती हैं, जो मनुष्य के आहार को आवश्यक पोषक तत्त्व प्रदान करती हैं ।
- मृदा संवर्द्धन: ये फसलें मृदा में **नाइट्रोजन** को स्थिर करती हैं, उर्वरता में सुधार करती हैं और अपनी **फलीदार प्रकृति** के कारण **सथि्टिक उर्वरकों** की आवश्यकता को कम करती हैं ।
- **जलवायु स्मार्ट फसल:** दलहन **सूखा-सहषिणु** (जल-गहन) फसलें हैं और कई अन्य फसलों की तुलना में इनमें **कार्बन फुटप्रिंट कम** होता है, जो स्थिरता में योगदान देता है ।
- **फसल स्वास्थ्य और चक्रण:** फसल चक्र में दालों को शामिल करने से मृदा की संरचना में सुधार होता है, रोग चक्र कम होता है और खरपतवारों को कम करता है, जिससे स्वस्थ कृषि प्रणालियों को बढ़ावा मिलता है ।

■ **संबंधित चिंताएँ:**

- **उपज में अंतर:** अन्य प्रमुख उत्पादकों की तुलना में भारत में दालों की **कम उत्पादकता**, जिससे मांग को पूरा करने के लिये आयात पर निर्भरता होती है ।
 - **न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum support price- MSP)** अधिक होने के बावजूद, प्रतएकड़ दाल की कम उपज होने के कारण दलहन उपजाने वाले किसानों की कमाई कम हो गई है ।
- **दलहन फसलों पर ध्यान न देना:** चावल व गेहूँ की खेती पर विशेष जोर देने के कारण दालों के लिये अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास और बुनियादी ढाँचा तैयार हुआ ।
- **उच्च आयात निर्भरता:** भारत को अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिये सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद कुछ दालों का आयात करने की आवश्यकता है, जिससे आत्मनिर्भरता प्रभावित हो रही है ।

■ **संबंधित सरकारी पहल:**

- [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन \(NFSM\)- दलहन](#)
- [प्रधानमंत्री अननदाता आय संरक्षण अभियान \(PM-AASHA\) योजना](#)
- [मूल्य स्थिरीकरण कोष](#)
- **तुअर दाल खरीद के लिये समर्पित पोर्टल:** जिसके माध्यम से किसान अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य या बाजार मूल्य पर NAFED एवं नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) को बेच सकते

